

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

23 / 2021  
25.02.2021

शिवराज पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी रोहित तहसील उनियारा जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला—टोंक

—रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय  
नायब तहसीलदार सोप दिनांक 27.01.2021 मिसल नम्बर 1451 / 2021

उपस्थिति : (1) श्री अशोक कासलीवाल, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय परोकार

निर्णय

दिनांक 30.11.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 27.01.2021 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1306, 1307 व 1437 रकबा 3.52 है०किस्म बारानी—2 वाके ग्राम रोहित तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 630/रु. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य का सही रूप से विवेचन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न ही मौके का निरीक्षण किया गया है। अपीलान्ट का किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। विवादित आराजीयात के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष वाद बाबत उद्घोषणा, दुरुस्ती, इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 47/2009 अपीलान्ट के पिता द्वारा पेश करने पर उक्त वाद का निर्णय दिनांक 21.09.2010 को न्यायालय द्वारा करते हुये वादी को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1306 व



जिला कलेक्टर  
टोंक

1307 का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया गया था, उक्त निर्णय की अपील न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के यहा प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2022 को निर्णय पारित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा का निर्णय व डिग्री दिनांक 21.09.2010 को यथावत रखा है। अपीलांट अपने पिता के जीवनकाल से विवादित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। अपीलांट के विरुद्ध पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1306, 1307 व 1437 रकबा 3.52 है 0किस्म बारानी-2 वाके ग्राम रोहित तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है, परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की स्वयं की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1306, 1307 व 1437 रकबा 3.52 है 0 किस्म बारानी-2 वाके ग्राम रोहित तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं 1627/2020 निर्णय दिनांक 16.03.2020 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 27.10.2022 को न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1437 रकबा 1.54 है 0 वाके ग्राम रोहित से कोई संबंध अथवा सरोकार नहीं है, उक्त आराजीयात पर मेरो कोई कच्चा-पक्का निर्माण भी नहीं है, उक्त आराजीयात पर कोई अतिक्रमण नहीं है और ना ही मैं भविष्य मे कोई अतिक्रमण करने की भावना रखूंगा।

विवादित आराजीयात के संबंध मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 21.09.2010 को वादी को आराजी खसरा नम्बर 1306 व 1307 का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया गया गया है, उक्त निर्णय की अपील न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के यहा प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा दिनांक 13.07.2022 को निर्णय पारित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा का निर्णय व डिग्री दिनांक 21.09.2010 को यथावत रखा है, परन्तु आराजी

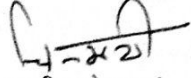


जिला कलेक्टर  
टोंक

खसरा नम्बर 1306 व 1307 वाके ग्राम रोहित आज दिनांक को भी सिवायचक ही दर्ज है। अपीलांट ने नवीन जमाबंदी भी प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित हो कि उक्त आराजी अपीलांट के खातेदारी में दर्ज हो गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप. का निर्णय दिनांक 27.01.2021 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(चिन्मयी गोपाल)  
जिला कलेक्टर, टोक